POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2021-23 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2022/अंक 09

मासिक प्रेषण दि. 8 सितम्बर, जी.पी.ओ., आरएमएस गांधी नगर, जयपुर-15

आज़ादी का अमृत महोत्सव

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 सितम्बर, 2022 मूल्य 50 पैसे

द्रौपदी मुर्मू ने संभाला राष्ट्रपति पद

देश में पहली बार आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के गौरवपूर्ण पद पर निर्वाचित हुई हैं। उन्होंने संसद भवन में राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और दोनों सदनों के सांसदों व देश के समस्त नागरिकों की आशा, अकांक्षा और अधिकारों के प्रति नए दायित्वों को निभाने के लिए आश्वस्त किया।

महामहिम ने विनम्रता के साथ सभी देशवासियों का अभिनन्दन किया, जो उनकी महानता और कर्तव्य बोध को दर्शाता है। महामहिम का संदेश है 'हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आजाद हिंदुस्तान के नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थी, उनकी पूर्ति के लिए इस अमृत काल में तेज गति से काम करना होगा। अमृत काल की सिद्धी का रास्ता दो पटरी पर आगे बढ़ेगा-सबका प्रयास और सबका कर्तव्य।'

भारत का गरीब सपने पूरे कर सकेगा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि मैंने देश के युवाओं के उत्साह और आत्मबल को करीब से देखा है। श्रद्धेय अटल जी कहा करते थे कि देश के युवा जब आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ अपना भाग्य नहीं बनाते, देश का भी भाग्य बनाते हैं। मैं जनजातीय समाज से हूं। वार्ड काउंसलर से लेकर भारत का राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। यह लोकतंत्र की जननी भारत वर्ष की महानता है।

उन्होंने कहा यह लोकतंत्र की ही शक्ति है एक गरीब घर की आदिवासी बेटी सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति पद तक पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, यह भारत के प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत का गरीब सपने भी देख सकता है और उसे पूरा भी कर सकता है।

दुनिया ने देखा है नए भारत को उभरते

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने पहले संबोधन में कहा कि दुनिया ने हाल के वर्षों में नए भारत को उभरते देखा है। हम स्वाधीनता के शताब्दी-उत्सव तक की 25 वर्ष की अवधि यानी भारत के अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा संकल्प है कि 2047 तक हम स्वाधीनता सेनानियों के सपनों को साकार कर लेंगे।

राष्ट्रपति ने कहा हमें जरूरतमंद तथा समाज के हाशिये पर रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए काम करना है। भारत के संविधान में हमारे राष्ट्रीय मूल्यों को नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में समाहित किया गया है। देश के प्रत्येक नागरिक से मेरा अनुरोध है कि वे अपने मूल कर्तव्यों के बारे में जानें, उनका पालन करें, जिससे राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छू सके।

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोंग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! मेरी एवं ग्राम गदर परिवार की ओर से देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हार्दिक अभिनन्दन। यह हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है कि एक गरीब आदिवासी वर्ग की बेटी जमीनी स्तर पर संघर्षमय जीवन बिताते हुए, देश के इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंची है। यह अवसर हम सभी को गौरवान्वित करता है।

भारत में आदिवासियों को भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में माना गया है। बोली जाने वाली भाषाओं, जनसंख्या का आकार, रहन सहन के ढंग को लेकर इनमें कई तरह की विविधताएं पाई जाती हैं। आजादी के बाद से पिछली सरकारों ने इनके विकास के लिए कई कानून और योजनाएं तो बनाई लेकिन उनकी सही तरह से पहुंच उन तक नहीं हो सकी। नतीजतन यह समुदाय राष्ट्रीय मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाया और गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन और रोजगार जैसी कई समस्याओं से जूझता रहा है। पिछले कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार ने जमीनी स्तर पर लोगों को ऊपर उठाने, उन्हें सशक्त बनाने के प्रयास शुरू किए हैं।

यह हमारा सौभाग्य है कि भारत के सभी पूर्व राष्ट्रपतियों ने प्रेरणादायक और परिपक्व नेतृत्व प्रदान कर पूरे विश्व में भारत को गौरवपूर्ण सम्मान और महत्वपूर्ण पहचान दिलाई है। इस वर्ष देश स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। समस्त देशवासियों को पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नेतृत्व गरीब, दलित, पिछड़े एवं आदिवासियों को सशक्त बनाने, उन्हें देश की मुख्यधारा से जोड़ने में सहायक होगा। भारत चहुंमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर होगा और विश्व में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा।

आदिवासियों एवं असहाय व्यक्तियों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता

आदिवासियों को भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जनजातियों में माना गया है। गरीब, निर्धन या असहाय व्यक्ति अपने वाजिब हकों के लिए न्याय पाने से वंचित न रहें, इसके लिए विधिक सहायता को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है:

- प्रदेश में 25 हजार रुपए प्रति माह की कमाई वालों को पैरवी के लिए मुफ्त वकील मिल सकता है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा) के अनुसार अब तीन लाख रुपए सालाना आय वालों को हाईकोर्ट सहित प्रदेश की किसी भी अदालत में पैरवी के लिए मुफ्त वकील मिल सकता है।
- इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मानव तस्करी, जातीय प्रताड़ना या हिंसा, प्राकृतिक आपदा के शिकार, औद्योगिक श्रमिक, बंदी एवं मनोरोग के शिकार व्यक्तियों को मुफ्त विधिक सहायता मुहैया कराने का प्रावधान है।
- महिलाओं के विवाह सम्बन्धी व दहेज विरोधी कानून, अपहरण, बलात्कार तथा भरण-पोषण भत्ता पाने के मामलों आदि में आमदनी की यह सीमा लागू नहीं होती। उन्हें अधिक आमदनी होने पर भी विधिक सहायता प्रदान की जा सकती है।
- विधिक सहायता के लिए पात्र व्यक्तियों को राज्य के किसी भी न्यायालय में दर्ज होने वाले मामलों में उनके वकील की फीस, कोर्ट फीस, गवाह खर्च आदि में से जो भी सहायता विधिक सहायता समिति दिलाना उचित समझे दिलाई जा सकती है।

छात्रा की मौत पर कॉलेज को देना होगा 25 लाख का जुर्माना

बेंगलुरू में मंड्डा एजुकेशन ट्रस्ट के वोग इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में स्वर्णा जसवंत ने 2010 में बीएसई एफडी कोर्स में दाखिला लिया था। सेकेंड ईयर में इंस्टीट्यूट बेंगलुरू रूलर स्थित नई निर्माणाधीन बिल्डिंग में स्थानांतरित कर दिया गया। वहां छात्रा स्वर्णा जसवंत की निर्माणाधीन बिल्डिंग से नीचे गिरने पर मौत हो गई। मामला राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में दाखिल हुआ।

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने कॉलेज प्रशासन की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए उन्हें आदेश दिया कि वह मृतक छात्रा के परिजनों को 25 लाख रुपए की राशि मुआवजे के तौर पर 9 फीसदी ब्याज सहित दे। आयोग ने कॉलेज प्रशासन की सभी दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि कॉलेज प्रशासन ने निर्माणाधीन बिल्डिंग में दूसरी मंजिल पर छात्र-छात्राओं को जाने से रोकने के लिए कोई प्रबंध नहीं किए थे। न तो वहां पर कोई दरवाजा लगाया गया था और न ही कोई रूकावट अथवा गार्ड को तैनात किया गया था। कॉलेज प्रशासन की लापरवाही से यह हादसा हुआ है और इसके लिए वह पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के लिए बाध्य है।

मनाया अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस

विश्व स्तर पर आदिवासी आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह उपलब्धि उन योगदानों को स्वीकार करती है जो आदिवासी लोग पर्यावरण संरक्षण जैसे विश्व के मुद्दों को बेहतर बनाने के लिए करते हैं।

इसे विशेष रूप से भारत के आदिवासियों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस का विषय 'पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका' था। भारत के सभी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में कार्यरत अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा इस दिन आदिवासियों के सशक्तिकरण, उनके अधिकारों व भलाई के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए।

आदिवासियों को जोड़ना होगा हुनर से

भारत में आदिवासी अपनी आजीविका के लिए जंगलों और खेतीहर मजदूरी में लगे हैं। रोजगार की कमी के चलते ज्यादातर आदिवासी अपने पारंपरिक काम-धंधे छोड़कर शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं। सरकारें हर साल आदिवासियों के लिए कई योजनाओं के तहत करोड़ों रुपए का बजट आवंटित करती हैं।

हालांकि सरकार ने कौशल व आजीविका विकास योजना के जरिए लोगों को हुनर से जोड़ने के प्रयास शुरू किए है। इस योजना को यदि खासतौर पर आदिवासी क्षेत्रों में तेजी से क्रियान्वित किया जाए तो यह उनके लिए काफी सहायक हो सकेगी।

देश में बढ़ रही है आदिवासी साक्षरता दर

अब देश में आदिवासी युवा पढ़ाई में आगे आने लगे हैं। हाल ही जारी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) 2022 के आंकड़े इसे उजागर करते हैं। वर्ष 1961 में आदिवासी साक्षरता दर सिर्फ 8.53 प्रतिशत थी। वर्ष 2021 में यह 71.6 प्रतिशत हो गई।

देश में 1200 से अधिक आश्रम स्कूल और 700 से ज्यादा एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों में हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। आदिवासियों के लिए अब विश्वविद्यालय भी खुले हैं। अब दौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से तेजी से शिक्षा का उजियारा उन तक पहुंचेगा और शिक्षा की अलख जगेगी।

देख सकते हैं गरीब मुझमें अपनी झलक

कक्षा की मॉनीटर से राष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाली द्रौपदी मुर्मू की सादगी राष्ट्रपति भवन पहुंचने के बाद भी कायम रही। वह संथाली साड़ी और सफेद हवाई चप्पल में शपथ लेने पहुंची। शपथ लेने के बाद महामहिम ने कहा कि मेरे इस निर्वाचन में देश के गरीबों का आशीर्वाद है। सदियों से वंचित और विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझमें अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। यह देश की करोड़ों गरीब महिलाओं और बेटियों के सपनों व सामर्थ की झलक है।

उन्होंने बताया कि संथाल क्रांति, पाइका क्रांति से लेकर कोल क्रांति और भील क्रांति ने स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समाज के योगदान को सशक्त किया था। सामाजिक उत्थान एवं देश-प्रेम के लिए 'धरती आबा' भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान से हमें प्रेरणा मिली है।

जन-धन योजना का उठाएं लाभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए शुरू की गई महत्वाकांक्षी जन-धन योजना के तहत करोड़ों खाते खुल चुके हैं। इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा के साथ-साथ ओवर ड्राफ्ट की सुविधा भी दी गई है। इन खातों के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं के हितलाभों व सरकारी सब्सिडी का नकद हस्तान्तरण भी शामिल है।

योजना आदिवासियों, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला वर्ग के लिए खासतौर पर लाभप्रद है। योजना के बारे में लोगों को जागरूक करना आवश्यक है।

'स्टैंड अप इंडिया' योजना है फायदेमंद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई 'स्टैंड अप इंडिया' योजना दलितों एवं आदिवासी समुदाय के लोगों का जीवन बदलने में सक्षम है। इससे नौकरी ढूंढने वाले नौकरी देने वाले बन सकते हैं।

योजना के तहत देश भर में फैली बैंकों की शाखाएं अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला वर्ग के उद्यमियों को कारोबार के लिए कर्ज उपलब्ध कराती है। इससे देश भर में नए उद्यमी पैदा हो सकते हैं।

योजना के तहत हर बैंक शाखा को नया उपक्रम लगाने के लिए 10 लाख से एक करोड़ रुपए तक के कम से कम दो ऋण बिना कुछ गिरवी रखे देने होते हैं। इस योजना का प्रसार-प्रचार आदिवासी जिलों में किया जाए तो लोग इसका फायदा उठा सकेंगे।

खुशी से झूमीं आदिवासी महिलाएं

पहली बार आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर प्रदेश के दूरस्थ आदिवासी बाहुल्य ग्रामीण इलाकों तक प्रसन्नता की लहर दिखाई दी।

प्रदेश के उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सिरोही और बारां जैसे कई जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रही आदिवासी समुदाय की महिलाएं खुशी से झूम उठी और अपनी पारंपरिक वेशभूषा में लोक गीत गाते और ढोल-नगाडों बीच नृत्य करते देखी गई। कई गांवों में पुरुष वर्ग ने भी उनका साथ दिया। उनसे बात की गई तो सामने आया कि उन्हें राष्ट्रपति से बहुत सारी आशाएं हैं।

कृषि क्षेत्र में लाई जाए नई योजनाएं

हमारे लिए यह गौरव की बात है कि इस बार आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनी हैं। मैं राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र उदयपुर संभाग के डूंगरपुर जिले से हूं। यह क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं से हमेशा वंचित रहा है। ज्यादातर लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिताते हैं। यहां रोजगार का अभाव हमेशा बना रहता है। रोजगार की तलाश में करीब 50 फीसदी लोगों पर पलायन की स्थिति बनी रहती है।

मैं इस क्षेत्र में रोजगार एवं आदिवासी व्यवस्थाओं में सुधार लाने और रोजगार देने वाली उन योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिनसे रोजगार बढ़े और लोगों का पलायन रुक सके। कृषि क्षेत्र में नई योजनाएं लाई जाए। जिससे सभी को आर्थिक मदद मिल सकेगी।

- हरीराम लबाना, डूंगरपुर

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोन: 228 2821 से 23 फैक्स: 0141-228 2485